भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. *774 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है

घरेलू पोत निर्माण उद्योग

774. श्री विनोद लखमशी चावड़ा :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्वदेशी पोत निर्माण उद्योग का आकार जापान, चीन और दक्षिण कोरिया की तुलना में बहुत छोटा है और दुनिया के 75 प्रतिशत पोत निर्माण ऑर्डर चीन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत की माल ढुलाई की क्षमता बहुत कम है जो अपनी मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है और देश को केवल वित्त वर्ष 2023 में समुद्री मार्ग से माल ढुलाई के रूप में विदेशी शिपिंग कंपनियों को 75 बिलियन डॉलर का भुगतान करना पड़ा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा दीर्घकालिक वित्तपोषण विकल्पों की सुविधा के लिए पीएलआई योजना शुरू करने और पोत निर्माण क्षेत्र को बुनियादी ढांचे के रूप में वर्गीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (घ): संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) की रिपोर्ट (2023) के अनुसार, सकल टनभार के मामले में वैश्विक पोतनिर्माण बाजार का 90% से अधिक जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के पास है।

(ङ) और (च): शिपयार्ड को अप्रैल, 2016 में पहले ही अवसंरचना का दर्जा दिया जा चुका है। इसके अलावा, "मेक इन इंडिया" नीति को बढ़ावा देने और भारत में पोतनिर्माण उद्योग में मदद करने के लिए मंत्रालय ने भारतीय शिपयार्ड के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार से ऑर्डर प्राप्त करने और वैश्विक ऑर्डर हासिल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने के लिए पोतनिर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी) योजना बनाई है। इस योजना में 1 अप्रैल, 2016 और 31 मार्च, 2026 के बीच हस्ताक्षरित पोतनिर्माण अनुबंधों के लिए भारतीय शिपयार्ड को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वित्तीय सहायता की दर शुरुआत में 2016 में 20% थी और यह घटकर 2026 में 14% तक रह जाएगी। अभी तक, 48 शिपयार्ड पंजीकृत हो चुके हैं, और 19 शिपयार्ड ने वित्तीय सहायता प्राप्त करके इस योजना का उपयोग किया है। इसके अलावा, 147 जलयानों के निर्माण और डिलीवरी के लिए 413.51 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

*****